

प्रेषक

प्रदीप सिंह रावत,
उप सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में

मुख्य अभियन्ता स्तर-1,
लोक निर्माण विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

लोक निर्माण अनुभाग-3

देहरादून: दिनांक 06 नवम्बर, 2009

विषय: वित्तीय वर्ष 2009-10 के आय-व्ययक में लेखाशीर्षक 3054 आयोजनेत्तर मद में 12वें वित्त आयोग के अन्तर्गत स्वीकृत कार्यों हेतु धनराशि अवमुक्त करने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या 4336/22 बजट (बा0वि0आ0-मार्ग अनुरक्षण कार्य)/09-10 दिनांक 16.10.2009 के संदर्भ में तथा शासनादेश संख्या 604/111(3)06- 01(सा0)06 दिनांक 12.09.2006, शासनादेश संख्या 716/111(3)06- 01(सा0)06 दिनांक 26.09.2006, शासनादेश संख्या 280/111(3)07- 01(सा0)06 दिनांक 30.05.2007, शासनादेश संख्या 523/111(3)07- 01(सा0)06 दिनांक 26.09.2007, शासनादेश संख्या 293/111(3)08-01(सा0)06 दिनांक 27.06.2008, शासनादेश संख्या 13/111(3)09- 01(सा0)06 दिनांक 02.03.2009 तथा शासनादेश संख्या 277/111(3)09- 01(सा0)06 टी.सी. V, दिनांक 04.06.2009 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2009-10 में द्वितीय किस्त के रूप में 12 वें वित्त आयोग के अन्तर्गत आय-व्ययक में अवशेष प्राविधानित धनराशि रुपये 4057.00 लाख के सापेक्ष रु0 3262.92 लाख (रुपये बत्तीस करोड़ बासठ लाख बयानवे हजार मात्र) की धनराशि को निम्न शर्तों के अधीन संलग्न सूची के अनुसार व्यय हेतु आपके निर्वहन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

- 1- आगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों की जाँच दरें शिड्यूल आफ रेट में स्वीकृत नहीं हैं, अथवा बाजार भाव से ली गई हो की स्वीकृति नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा। कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वन भूमि एवं निजी भूमि आदि की कार्यवाही की जाय तथा भूमि का भुगतान नियमानुसार प्रथम वरीयता के आधार पर किया जाय एवं भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित कर कब्जा प्राप्त करने के उपरान्त ही कार्य प्रारम्भ किया जाय। स्वीकृत की जा रही धनराशि से 12वें वित्त आयोग के अन्तर्गत संलग्न सूची में अंकित कार्यों पर एवं कार्यवार आवंटित धनराशि की सीमा तक किया जायेगा।
- 2- कार्य कराने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करने के बाद ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
- 3- कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना की स्वीकृत नार्म है, स्वीकृत नार्म से अधिक व्यय कदापि न किया जाय क्योंकि इस स्वीकृति में धन एवं समय में बढोतरी संभव नहीं होगी।
- 4- एकमुश्त प्राविधान को कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक होगा।

52/1114

- 5- कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि के मध्य नजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टों के अनुरूप ही कार्यों को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करें।
- 6- कार्य कराने से पूर्व स्थल का भली भाँति निरीक्षण उच्चाधिकारियों एवं भूगर्भवेत्ता के साथ अवश्य करा ले। निरीक्षण के पश्चात् स्थल आवश्यकतानुसार निर्देशों तथा निरीक्षण टिप्पणी के अनुरूप कार्य किया जाय।
- 7- आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृत की गई है, व्यय उसी मद में किया जाय, एक मद का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाय।
- 8- निर्माण सामग्री को प्रयोग में लाने से पूर्व किसी प्रयोगशाला से टेस्टिंग करा ली जाय, तथा उपयुक्त पायी जानी सामग्री को प्रयोग में लाया जाय।
- 9- स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण तब ही किया जायेगा जब भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित कर उस पर कब्जा प्राप्त हो जाय और योजना हेतु पूर्व में अवमुक्त धनराशि का 90 प्रतिशत उपयोग कर लिया गया हो। यदि कब्जा नहीं प्राप्त होता है तो उसकी सूचना शासन को देकर समस्त धनराशि शासन को समर्पित कर दी जायेगी।
- 10- यदि उक्त कार्यों में से किसी कार्य हेतु लोक निर्माण विभाग के बजट से अथवा अन्य विभागीय बजट से कोई धनराशि स्वीकृत की जा चुकी है तो उस योजना हेतु इस शासनादेश द्वारा स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण न करके धनराशि शासन को समर्पित कर दी जायेगी।
- 11- व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत शासकीय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता हो उनमें व्यय करने से पूर्व प्रत्येक कार्य के आगणनों/पुनरीक्षित आगणनों पर प्रशासकीय एवं वित्तीय अनुमोदन के साथ-साथ विस्तृत आगणनों पर सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति भी प्राप्त कर ली जाय। स्वीकृत की जा रही धनराशि का दिनांक 31.03.2010 तक उपयोग सुनिश्चित करके राज्य सरकार के वित्त आयोग प्रकोष्ठ व भारत सरकार को उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रेषित किये जायेंगे। कार्य कराते समय उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 एवं उक्त के क्रम में समय-समय पर निर्गत दिशा-निर्देशों का भी अनुपालन किया जाय।
- 12- कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता के लिये सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।
- 13- स्वीकृत कार्यों पर व्यय 12 वें वित्त आयोग के दिशा निर्देशों के अनुसार ही किया जायेगा।
- 14- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2009-10 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या 22 के लेखा शीर्षक 3054 सड़क तथा सेतु-04 जिला और अन्य सड़कें-आयोजनेत्तर 337 सड़क निर्माण कार्य-01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरानिधानित योजना 01-12 वें वित्त आयोग द्वारा प्रदेश के मार्गों/पुलियों के अनुसूचन-29 अनुसूचन मद के नाम में डाले जायेगा।
- 15- यह आदेश वित्त अनुभाग-2 के अशासकीय संख्या 315/XXVII/(2)/2009 दिनांक 06 नवम्बर, 2009 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

संलग्न :- यथोक्त।

भवदीय,

(प्रदीप सिंह रावत)
उप सचिव।

प्रदीप सिंह रावत

पु.सं. 623 (1)/111(3)09 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार (लेखा प्रथम), उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
3. आयुक्त गढ़वाल/कुमायूं मण्डल, पौड़ी/नैनीताल।
4. समस्त जिलाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
5. स्टाफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
6. अपर सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड शासन।
7. समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
8. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, उत्तराखण्ड देहरादून।
9. मुख्य अभियंता स्तर-2, लोक निर्माण विभाग, कुमायूं/गढ़वाल, अल्मोड़ा/पौड़ी।
10. सम्बन्धित अधीक्षण/अधिशाली अभियंता, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड।
11. वित्त अनुभाग-2/वित्त नियोजन प्रकोष्ठ, उत्तराखण्ड शासन।
12. लोक निर्माण अनुभाग 1 व 2, उत्तराखण्ड शासन।
13. गार्ड बुक।

आज्ञा से,

11/11/11

(महिमा)

अनु सचिव।